भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *310
22.07.2019 को उत्तर के लिए

वैश्विक तापमान में वृद्धि का आसन्न खतरा

***310. श्री संजय सिंह:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक तापमान में वृद्धि के खतरे के संबंध में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण होने वाली संभावित क्षति का आकलन करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) क्या ऐसी कोई योजनाएं और/अथवा नीतियां हैं जिनमें वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि से निपटने के लिए नागरिकों को भी शामिल किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

''वैश्विक तापमान में वृद्धि का आसन्न खतरा'' के संबंध में श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 22.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *310 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) सरकार द्वारा नागरिकों को शामिल करने और जलवायु परिवर्तन के विषय में उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) द्वारा समाज के सभी वर्गों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय हरित फसल (एनजीसी) कार्यक्रम के तहत, लगभग एक लाख स्कूलों को ईको-क्लबों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, जिनमें लगभग 33 लाख छात्र पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं।

ii) भारत का सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन जागरूकता कार्यक्रम 'विज्ञान एक्सप्रेस जलवायु योजना विशेष ट्रेन' (एसईसीएएस)-जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक चल प्रदर्शनी- है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच, विशेष रूप से छात्रों में जागरूकता पैदा करना है। एसईसीएएस का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन संबंधी विज्ञान, जलवायु परिवर्तन के प्रेक्षित एवं प्रत्याशित प्रभावों और विभिन्न संभव उपायों की जानकारी में वृद्धि करना है। दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 से 7 मई, 2016 के दौरान, इस ट्रेन ने लगभग 19,800 कि.मी. की दूरी तय की थी और 23.24 लाख से अधिक आगंतुकों ने इस प्रदर्शनी का लाभ उठाया। ट्रेन द्वारा प्राप्त अभूतपूर्व रिस्पांस के कारण उसे पुन: दिनांक 17 फरवरी, 2017 से 08 सितम्बर, 2017 तक 19,000 कि.मी. की दूरी तय करने के उद्देश्य से चलाया गया।

iii) वहनीय जीवन-शैलियां अपनाने में नागरिकों को शामिल करने हेतु, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ऊर्जा की बचत करने, जल को संरक्षित करने, पेड़ लगाने, पुन:उपयोग तथा पुनर्चक्रण में कमी करने, जहां संभव हो कार-पूलिंग करने और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने जैसे छोटे-छोटे कदमों, जिनके माध्यम से लोग जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने में योगदान कर सकते हैं, पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक सामाजिक आंदोलन 'अच्छे हरित कार्य' की शुरूआत की गई।

iv) इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली और उसके मैसूरू, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई-माधोपुर में स्थित चार क्षेत्रीय संग्रहालयों द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न जनसंपर्क कार्यकलापों, विषय-आधारित प्रदर्शनी गैलरियों आदि के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने में भी शामिल रहा है।

v) हिमालयी पारि-प्रणाली के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई) और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी) के तहत, 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 25 राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों को सहयोग प्रदान किया गया है और इन राज्य प्रकोष्ठों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य वैश्विक तापन के खतरे के विषय में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों द्वारा संचालित जन-जागरूकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1.5 लाख लोगों को वैश्विक तापन के संबंध में जागरूक बनाया गया है।

vi) भारत विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का वैश्विक मेजबान देश था। इस समारोह के दौरान, दिल्ली-एनसीआर के 200 स्कूलों के 10,000 स्कूली बच्चों ने एनविथोन-द ग्रीन रन में भाग लिया।

vii) सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुकूलन उपायों में सहयोग प्रदान करने हेतु भी एक योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा आयोजित ध्यान-केंद्रित कार्यशालाओं के माध्यम से हितधारकों और स्थानीय एजेंसियों का क्षमता निर्माण शामिल है।

(ख) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने हेतु, भारत सरकार द्वारा एक अध्ययन ''जलवायु परिवर्तन और भारत: एक 4x4 आकलन- वर्ष 2030 के दशक के लिए एक विषयगत एवं क्षेत्रीय विश्लेषण'' की रूपरेखा तैयार की गई है। इस अध्ययन में, वर्ष 2030 के दशक के लिए चार प्रमुख विषयों अर्थात् कृषि, जल, प्राकृतिक पारि-तंत्र, जैव विविधता और स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रेक्षित जलवायु और जलवायु परिवर्तन के अनुमानों के संबंध में भारत के चार प्रमुख क्षेत्रों, नामत: हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय संप्रेषणों के भाग के रूप में, मंत्रालय द्वारा भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में अध्ययन कराए गए थे जिनका सार 'संवेदनशीलता आकलन और अनुकूलन' अध्यायों में दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा भी जलवायु के अनुकूल कृषि संबंधी राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) अनुमान के तहत कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में अध्ययन कराए गए थे।

(ग) और (घ) वैश्विक तापन के विषय में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने हेतु भारत के राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी), जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी), जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) और जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (सीसीएपी) शामिल हैं, का एक अभिन्न अंग है।

*****